Newspaper Clips

July 23, 2013

HINDUSTAN ND 23-Jul-13 P-10

चमक खो रहा है ब्रांड आईआईटी

प्रवेश परीक्षा के नए पैटर्न ने आईआईटी से वह सब छीन लिया, जिसके लिए इस संस्थान की दुनिया भर में साख थी।

एक जमाना वह भी था, जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जनरल वेस्ले क्लार्क ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह घोषणा की थी कि अमेरिका में जो भी छात्र आईआईटी से पढ़ाई पूरी करके आएगा, उसे तत्काल अमेरिकी ग्रीनकार्ड दे दिया जाएगा। मशहूर अखबार द *न्यूयॉर्क टाइम्स* में साल 2005 में प्रकाशित एक लेख में कहा गया था कि आईआईटी में प्रवेश अमेरिका के हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने से भी अधिक कठिन है। आईआईटी के गौरव का अंदाजा लगाने के लिए ये दो ही उदाहरण काफी हैं। लेकिन आखिर आईआईटी को हो क्या गया है? क्यों कल तक गौरव का विषय रहे आईआईटी संस्थान में कई बच्चे अपना दाखिला नहीं कराना चाह रहे हैं? आखिर बात क्या है कि इस बार आईआईटी की 769 सीटें खाली रह गईं?

कुछ साल पहले तक जहां आईआईटी के एक स्टूडेंट को पढ़ाई पूरी करने से पहले औसतन दो से तीन नौकरियों का प्रस्ताव मिल जाता था और वे खुद तय करते थे कि उनमें से कौन सी नौकरी अच्छी है और किस में कितना पैकेज मिल रहा है। आज वहीं, आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बावजूद आधे से ज्यादा विद्यार्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो क्या ब्रांड आईआईटी अब अपनी अहमियत खो रहा है? पिछले वर्षों में नारायण मूर्ति जैसे उद्योग जगत के महारथी ने भी आईआईटी की ब्रांड वैल्यू पर प्रश्न खड़े किए। इतना ही नहीं, इस वर्ष आईआईटी की नई चयन-प्रक्रिया इतनी अव्यावहारिक थी कि आईआईटी प्रवेश प्रक्रिया पास करने के बावजूद 79 विद्यार्थियों के इसमें पढ़ने के सपने साकार नहीं हो सके। आईआईटी की घटती लोकप्रियता और इसकी जटिल चयन-प्रक्रिया एक गंभीर चिंता का विषय है। आईआईटी को लेकर हमारी पूरी सोच बदलाव की मांग कर रही है।

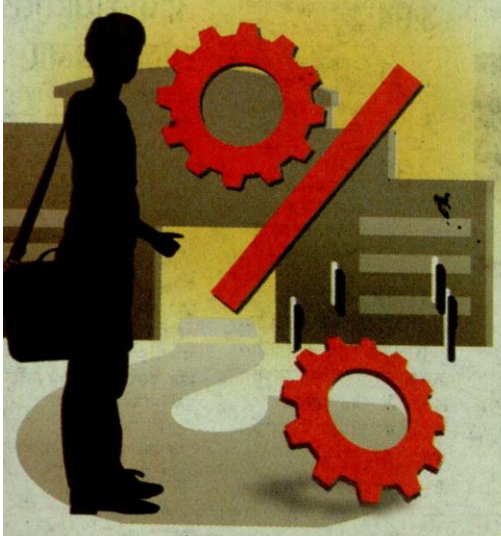

डी. श्रीनिवास

कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत छोटे फैसलों से होती है। जाने वह कौन-सी घड़ी थी, जिसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा में बदलाव का बिगुल फूंका। किसे पता था कि यह बदलाव आईआईटी के इतिहास से लेकर वर्तमान तक को बदल देगा और लोग इन आईआईटी में नामांकन के बदले कुछ दूसरे संस्थानों में दाखिले को ज्यादा गौरव की बात समझेंगे? इसका अंदेशा पहले से ही था, तभी तो आईआईटी की प्रवेश परीक्षा के नए पैटर्न का विरोध किया गया था। इस संबंध में मैंने तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से कई मुलाकातें की थीं और

आनंद कुमार
संस्थापक, सुपर-30

उन्हें यह समझाने का प्रयास किया था कि यह नया फॉर्मूला न केवल विफल होगा, बल्कि यह गरीब विरोधी भी होगा।

तब सरकार ने पहली बार यह फैसला किया था कि एक राष्ट्र-एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और वही परीक्षा आईआईटी समेत देश के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले का आधार बनेगा। इस परीक्षा में 12वीं कक्षा के अंक को जोड़कर नतीजे प्रकाशित का निर्णय लिया गया। और फिर आईआईटी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा में सफल होना तो जरूरी था ही। साथ ही, 12वीं कक्षा के विभिन्न बोर्डों में टॉप 20 पर्सेंटाइल के रेस में होना भी एक अनिवार्यता थी। इस फैसले ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। गरीब तबके के बच्चे, जिनमें नैसर्गिक प्रतिभा-क्षमता तो थी, मगर जो स्कूलों की भारी-भरकम फीस वहन नहीं कर सकते थे, इस दौड़ में पिछड़ने लगे। साथ ही, पर्सेंटाइल निकालने का तरीका इतना विवादास्पद और जटिल है कि आज भी कई विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक इसे नहीं समझ पाए हैं।

यही नहीं, मौजूदा पद्धति में यह भी कहा गया है कि आईआईटी में प्रवेश के लिए दो अलग-अलग परीक्षाएं होंगी- मेन और एडवांस। सरकार के इस फैसले से विद्यार्थियों पर न केवल दबाव बढ़ा है, बल्कि कोचिंग माफियाओं के घर की खिड़की सीधे बाजार में खुल गई। सीधे-सीधे समझें, तो अब बच्चों को पहले की अपेक्षा अधिक कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। एक कोचिंग बारहवीं की परीक्षा के लिए, एक मेन टेस्ट के लिए और फिर एक एडवांस टेस्ट के लिए। संपन्न घर के बच्चे तो कोचिंग के फायदे उठा रहे हैं, लेकिन बेचारे निर्धन इस दौड़ में पिछड़ते हुए महसूस कर रहे हैं। हालांकि, उस वक्त मानव संसाधन मंत्रालय के इस दावे को भी मैंने गलत बताया था कि नए पैटर्न में कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आज भारत के आगे सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि दुनिया के 100 श्रेष्ठ कॉलेजों की सूची में आईआईटी को कैसे प्रवेश मिले। एक बड़ी सच्चाई यह है कि बाजार आज मंदी के दौर से गुजर रहा है। छात्रों के बीच चुनौती इस बात की है कि वे अच्छे कॉलेजों से पढ़ाई करें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे, तो किसी अच्छी कंपनी में उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। बगैर अच्छे शिक्षक, भवन और संसाधनों के पिछले कुछ वर्षों में कई नए आईआईटी धड़ाधड़ खुल गए हैं। लिहाजा उन आईआईटी में, जिनकी रैंकिंग, फैकल्टी अच्छी नहीं है और जिनमें पढ़ाई की विकसित सुविधाएं नहीं हैं, वहां दाखिला लेने से छात्र कतरा रहे हैं और वे अन्य कॉलेजों में नामांकन ले रहे हैं।

स्थितियां इससे भी बुरी न हों, इसके लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। यकीन मानिए, कोई भी समस्या उसके समाधान से बड़ी नहीं होती। आज जरूरत इस बात की है कि त्वरित फैसले लेकर बदलाव किए जाएं। आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए सिर्फ दो मौके मिलते हैं, जिसका लाभ ग्रामीण तथा निर्धन छात्र को नहीं मिल पाता है। जानकारी के अभाव में कमजोर तबके के विद्यार्थियों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता और जब तक उन्हें जानकारी मिलती है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब गांव-देहात की प्रतिभाओं के लिए आईआईटी जैसे संस्थानों तक का सफर बहुत कठिन हो गया है।

प्रवेश परीक्षा में बैठने के दो मौकों की जगह कम से कम तीन मौके दिए जाने चाहिए। आईआईटी में मूल्यांकन की जटिल पद्धति को बदलकर उसका सरलीकरण किया जाना बहुत जरूरी है। वैसे बच्चों को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, जो 60 फीसदी अंक लाते हों। आईआईटी में प्रवेश की परीक्षा को अन्य दूसरी परीक्षाओं से दूर रखा जाए, ताकि इसकी गरिमा अक्षुण्ण रखी जा सके। किसी भी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा सिर्फ पूर्व-स्नातक तक की पढ़ाई पर निर्धारित नहीं की जा सकती है। नए खोले गए आईआईटी में भी अच्छे शोध और पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, इसके लिए अच्छे शिक्षकों की बहाली और उनकी निरंतर ट्रेनिंग की जरूरत पर ध्यान देना होगा। अगर वक्त रहते सरकार यह कदम नहीं उठाती, तो आने वाले समय में आईआईटी में खाली सीटों की संख्या में और इजाफा होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan Times ND 23-Jul-13
P-8

TECH GLITCHES AND MERIT VIOLATIONS MAR NIT ADMISSIONS

Vanita Srivastava
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The admissions to the National Institutes of Technology (NITs) have been mired by large-scale merit violations and tech glitches this year.

After 'false' seat allotments to more than one lakh students due to tech glitch, the admission body had to roll back its second upgradation list on Monday after large scale merit violations surfaced.

The counseling for NIT seats is being done by the Central Seat Allocation Board (CSAB). There are nearly 20,000 seats for 30 NITs.

"Yes we have noticed large-scale merit violations and have therefore decided to roll back the second upgradation list announced on Monday. We have also decided to have a third round of seat allotment. We had actually not anticipated the degree to which merit violations could happen," Prof Sunil Kr Sarangi, chairman, CSAB 2013, said.

The violations happened since an upgradation of seats was done to minimise vacancies but, in the process, some got advantage over others, he said.

Earlier, more than one lakh students were on July 18 'wrongly' allotted mechanical engineering branch at NIT Patna against the 93 seats actually available.

The error was noticed in an hour and corrected. Soon after, the chairman tendered an apology on the official website for the faulty allotments. This was the second apology letter. The first came after the first round of counselling where a tech glitch changed the institute and seats alloted to the students.

Admitting that errors had occurred during NIT counseling, Sarangi said: "Till last year, we were taking computer support from the NIC. This year to reduce vacancies, there was a plan to have a common counselling for IIT and NIT with computational support of CDAC."

DON'T CALL UP WARDS FREQUENTLY, IIT-K TELLS PARENTS

HT Correspondent
htcitykanpur@hindustantimes.com

KANPUR: After asking B Tech (first year) students not to use their personal laptops in the institute, the IIT Kanpur administration has come up with another word of advice -- this time for the parents.

The director of the premier institute Dr Indranil Manna, during an interaction with parents on Monday, advised them not to make frequent calls to their wards and avoid discussing family problems with them.

This, he said, was to allow the students to focus on their studies and nothing else.

"Besides, the parents should not pressurise their wards for achieving higher grades, as this often puts extra burden on them and this, in turn, leads to depression," he said.

He also allayed the fear of some parents about the placement scenario and said the institute was way ahead then some other institutions.

He also had some words of wisdom for the new batch of B Tech students.

"Students should not hesitate in sharing their problems, even petty ones, with their colleagues and even teachers. They should not feel aloof during their stay at the institute," he said.

In case of any difficulty in coping up with the teaching of a particular subject, or any other issue, they should discuss it with the members of the counselling cell. **CONTINUED ON PAGE 9**

DON'T CALL UP WARDS ...

CONTINUED FROM PAGE 1

He also told the students to be disciplined and focused on their goals.

During the interaction, head of counselling cell Dr Mukesh Sharma urged the students to attend personality development courses at the institute for their overall growth.

He also said in order to reduce home sickness syndrome among the students who have for the first time come to live in a hostel, the institute had proposed to adjust two students in a room so that they could share their feelings.

Times of India ND 23-Jul-13 P-7

President asks HRD ministry to fill vacancies

There is a shortage of faculty to the extent of 38 per cent in 43 central universities managed by the ministry of Human Resource Development

Taking note that there were nearly 38 per cent teaching vacancies in central universities, President Pranab Mukherjee has asked the HRD ministry to fill the positions with the best of faculties. "We are having 43 central universities managed by the ministry of Human Resource Development (HRD)...I find there is a shortage of faculty to the extent of 38 per cent in these universities.

I have requested the HRD minister to take expeditious steps in filling the vacancies. We require quality teachers and we must provide incentives, so that bright students join the teaching profession," Mukherjee said while speaking at a convocation ceremony recently.

There is a need to use technology in spreading quality education across the country, said Mukherjee while stressing that lectures of the best of faculties could be taken to remote areas through electronic technology.

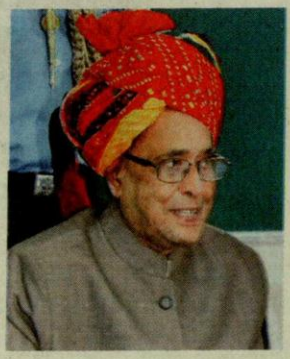

He also said, at a time of fierce competition, innovation has to be encouraged and that there was a need to expand the physical infrastructure related to education and also raise its quality. The President noted that in a recent survey conducted by an agency, none of the country's top educational institutions figured among the world's top 200.

This was not always the case and at one time Indian universities like Takshshila and Nalanda attracted scholars from around the world, Mukherjee said. "History has shown that how nations have risen from ashes, from mediocrity, from clutches of underdevelopment on the foundation of a strong knowledge system. In contemporary times marked by technological and economic advancement, knowledge is an important channel for shaping the destiny of nations," he said.

ECONOMIC GROWTH DEPENDS ON A SUCCESSFUL MOBILISATION OF THE KNOWLEDGE ECONOMY, HE SAID

"Economic growth depends on a successful mobilisation of the knowledge economy, which in turn has its basis in a robust education system," he added. Addressing the students who had graduated, Mukherjee said, the nation had invested in them, but did not want big sacrifices in return.

The nation only asks you to understand your duties and responsibilities well, he said.

Earlier, while commenting on the spurt in crimes against women at another convocation ceremony, he had said that these incidents had shaken the collective conscience of the nation and educational institutes should act to take on the moral challenges the country faces.

"The recent increase in cases of brutal assault on women and children has shaken the collective conscience of our nation. These unfortunate incidents call for effective measures to ensure their safety and security," Mukherjee said.

"It also highlights the need for us to bring such degradation of values to an immediate halt. Our institutes, beginning from schools, must act as guides in meeting the contemporary moral challenges," he added.

Mukherjee said India today stands at "the cusp of greatness" where there were challenges but also enormous opportunities ahead.

"Science and technology is duly recognised as the vehicle to take India into the front ranks of the nations of the world. We have to build a large pool of scientific and technical manpower to aid our progress". The President also said the country has a growing young population and within a decade it was likely to have the largest workforce in the world. This demographic transformation must be leveraged by us by expanding technical education in the country, he said.

He, however, said "the higher education sector in India today does not have enough good quality institutions to meet the growing aspirations of our youth".

"Along with measures to increase quantity, the drive to enhance the quality of education should engage the attention of our policy makers," Mukherjee said.

EducationTimes 15TH ANNIVERSARY

Deccan Herald ND 23.07.2013 P-7

Centre asks states to get higher educational institutions accredited

Despite rule, many institutions are yet to apply for accreditation

NEW DELHI: The Centre has asked state governments to impress upon all higher educational institutions functioning under them to get accredited. A majority of these institutes are yet to apply for accreditation despite the University Grants Commission (UGC) making it mandatory.

According to sources, at a meeting of the state higher education secretaries here, the Human Resource Development (HRD) Ministry suggested them to disseminate amongst the state higher educational institutions the need to undergo assessment and accreditation.

The Ministry also asked the states to familiarise the institutions with the processes required for seeking accreditation, assuring them of full support by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and the National Board of Accreditation (NAC).

"A large number of institutions are yet to apply for accreditation despite the notification issued by the UGC in March. The role of state governments is significant in getting all the institutions accredited as it would enable the higher education system of the country to become a part of the global quality assurance system," a HRD Ministry official said. Recently, the UGC made assessment and accreditation of higher educational institutions mandatory across the country. The HRD Ministry decided to introduce it through an executive order as the National Accreditation Authority Bill is pending in Parliament for nearly three years.

'It would enable the higher education system of the country to become a part of the global quality assurance system'

The All India Council for Technical Education (AICTE) has also approved regulations for mandatory assessment and accreditation of technical institutions. "These will be notified shortly," a HRD Ministry official said. The Ministry suggested the states to adopt mandatory accreditation as one of the norms for deciding state funding in the days to come. The Ministry also asked the states to explore formation of credible assessment and accreditation agencies, sources privy to the meeting of state secretaries said.

At the meeting, the Ministry told the states that accreditation agencies should be registered as non-profit entity. They should be academically and financially an autonomous body. "In this regard, required assistance can be extended by NAAC or NBA. Funding can be extended through Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan," sources added.

"Till the formation of the National Accreditation Regulatory Authority, the UGC and AICTE will be the body according recognition to the state accreditation agencies. The procedure outlined in the Bill will be applied for according recognition to the institutions," a Ministry official said.

DH News Service